

(78)

अनुमोदन हेतु प्रारूप  
पत्रक-  
बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक: 2386 या.वि.पटना दिनांक: 26/5/05  
या.वि.-7/ई.आ.यो.(मा.नि.)-06/2004

प्राप्त  
कै.ए.एच.सुब्रमणियन्,  
मुख्य सचिव ।

सेवा में  
समी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका की कडिका 4.4.1 में संशोधन के आलोक में  
आपदा प्रभावित परिवारों को यथाशीघ्र इंदिरा आवास उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में कहना है कि आप अवगत हैं कि इंदिरा आवास की मार्गदर्शिका की कडिका 4.4.1 में निहित प्रावधान के अनुसार प्राकृतिक आपदा तथा आकरमिक परिस्थिति यथा दंगा, खून-खराबा आगजनी आदि जैसी परिस्थिति विशेष से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के स्तर पर इंदिरा आवास योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य का 5 प्रतिशत निधि कर्णांकित रहता है । इस कर्णांकित निधि से राशि की विमुक्ति प्रत्येक जिला के 5000 लाख (पचास लाख) रुपये की सीमा तक जिला से प्राप्त प्रस्ताव विभागीय अनुशंसा के साथ भारत सरकार को प्रेषित किये जान पर किया जाता था तथा भारत सरकार से राशि की विमुक्ति के पश्चात् देय अनुपातिक राज्यांश की विमुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती थी ।

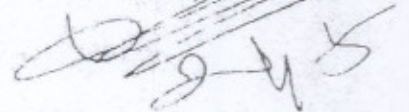
उपरोक्त जटिल प्रक्रिया को देखते हुये तथा प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत पहुँचाने के उद्देश्य से भारत सरकार के पत्रांक-एच.-11011/6/2004-आर.एच.(पी.) दिनांक-15.04.2005 (प्रति संलग्न) द्वारा मार्गदर्शिका की कडिका 4.4.1 में संशोधन करते हुये जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है कि जिला स्तर पर इंदिरा आवास योजना (केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित) अथवा अन्य स्रोत की उपलब्ध राशि से ऐसे पीडित परिवारों के क्षतिग्रस्त मकानों का निर्माण कराकर उन्हें पुनर्वासित करें । इस निमित्त

लाभानवितों के लिए अन्य शर्तें इन्दिरा आवास योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार पूर्ववत् रहेगी। इस मद में जो राशि व्यय होगी उसकी प्रतिपूर्ति के लिये जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पूर्व निर्धारित सूचनाओं सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किये जायेंगे तथा भारत सरकार द्वारा इस राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

भारत सरकार द्वारा किये गये उक्त संशोधन से स्पष्ट है कि पीड़ित परिवारों को तत्काल ही पुनर्वासित करने में दिव्य को देखते हुये सशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है। अस्तु इस संबंध में आपके पत्र से पूरे संबन्धनशीलता के साथ इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

अतः आप इस दिशा में पूरी तन्परता के साथ ध्यान दें तथा पीड़ित परिवारों को तत्काल ही सहाय्य देने के लिये उनके अस्थिर आवासों का निर्माण कराकर उन्हें पुनर्वासित करें तथा राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित करते हुये उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करावें ताकि विभाग स्तर से भी उसका अनुश्रवण हो सके।

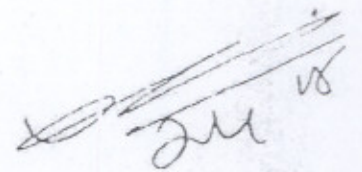
विश्वामाकान



ज्ञापक- 2886

मुख्य सचिव  
दिनांक- 26/5/65

प्रतिनिधि--(अनुलग्नक सहित) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप विकास आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



मुख्य सचिव